गौमाता राष्ट्रमाता
स्वतः स्फूर्त गौ-प्रतिष्ठा आन्दोलन
Visit : www.1008.guru / Ph. : 7417417414

हिंदी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No.: MAHHIN/2008/24084 ■ www.rashtriyaswabhimaan.com

वर्ष : 17 | अंक : 234 | मुंबई, गुरुवार, 14 मई 2026 | पृष्ठ : 4 | मूल्य 1 रुपए

संक्षिप्त ख़बरें

प्रधानमंत्री के 'एक साल तक सोना न खरीदें' के आह्वान से भिवंडी के सर्राफा व्यापारी नाराज

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता

भिवंडी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से बचत की अपील करते हुए यह आह्वान किया है कि वे एक साल तक सोने की खरीदारी न करें। इस अपील के बाद देश भर के सर्राफा व्यवसायियों और स्वर्ण कारीगरों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसका बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी होगा।

इस निर्णय को लेकर भिवंडी सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राज्य संगठन के उपाध्यक्ष प्रदीप (पप्पू) राका ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनके अनुसार इस फैसले की सबसे ज्यादा मार छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों पर पड़ेगी। सोने की कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ें, नागरिक भविष्य की बचत के नजरिए से सोने में निवेश करते हैं। इससे शेयर बाजार के साथ-साथ दुकानदारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरकार को सबसे पहले नागरिकों को इस निर्णय के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। प्रदीप राका ने आगे कहा कि वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में नागरिकों को चाहिए कि वे पुराने सोने का नया ज़ेवर बना करके उसका उपयोग करें। इससे सोने का आयात कम होगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ-साथ दुकानदारों का नुकसान भी नहीं होगा। ₹सरकार को नागरिकों को इस फैसले की गहराई समझानी चाहिए ताकि बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा न हो।

— प्रदीप (पप्पू) राका (अध्यक्ष, भिवंडी ज्वेलर्स एसोसिएशन)

सरकार ने CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल फिर एक साल बढ़ाया

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सीबीआई (CBI) के वर्तमान डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा उन्हें यह सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले भी प्रवीण सूद को एक साल के सेवा विस्तार दिया गया था। अब वह इस पद पर मई 2027 तक बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल फिर से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया। सूद ने 25 मई 2023 को दो वर्ष की अवधि के लिए सीबीआई डायरेक्टर का पदभार संभाला था। इससे पहले मई 2025 में भी उनको एक साल के सेवा विस्तार दिया गया था, अब वह इस पद पर मई 2027 तक बने रहेंगे। सरकार की ओर से जारी बयान में मुताबिक, उनके कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई चयन समिति की बैठक में लिया गया। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों की मंत्रिमंडलीय समिति (एसीसी) ने एक वर्ष की अवधि के लिए सूद के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी। वहीं इससे पहले इस बैठक से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वे रबर स्टैंप नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मैं इस पक्षपाती प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे मजबूत शब्दों में असहमति जताता हूं। राहुल ने सरकार पर विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और आलोचकों को लक्षित करने के लिए प्रमुख जांच

महर्षि महेश योगी फाउंडेशन जमीन घोटाले की जांच करेगी SIT, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की देखरेख में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है. यह दल स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जमीनों की कथित धोखाधड़ी से हुई बिक्री की जांच करेगा. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस अंतरिम निर्देश को रद्द कर दिया है, जिसमें पुलिस को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया गया था.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि हालांकि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान किसी आरोपी को दंडात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए अदालत विवेक का प्रयोग कर सकती है, लेकिन जांच एजेंसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193(3) के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल न करने का निर्देश देना इस मामले के तथ्यों के आधार पर अनुचित था.

यह फाउंडेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन (TM) और आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है. इसके संस्थापक महर्षि महेश योगी की मृत्यु के बाद इसमें आंतरिक गुटबाजी शुरू हुई, जिसमें दो राइवल अजय प्रकाश श्रीवास्तव और चंद्र मोहन से जुड़े समूह सोसाइटी के नियंत्रण और जमीनों पर दावा करने लगे.

नतीजा यह हुआ कि फर्जी दस्तावेजों, जाली पावर ऑफ अटॉर्नी और फर्जी रिकॉर्ड के जरिए सोसाइटी की फ्री होल्ड जमीनें करोड़ों रुपये में बेच दी जा रही हैं, जो सोसाइटी के मूल उद्देश्यों (मानव कल्याण और आध्यात्मिक कार्य) के पूरी तरह खिलाफ है.

महंगाई का बड़ा झटका!

अमूल और मदर डेयरी का दूध हुआ महंगा, नई कीमतें आज से होंगी लागू

नई दिल्ली। अमूल ब्रांड के तहत प्रोडेक्ट्स बेचने वाले गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने बुधवार को भारत भर में दूध की कीमतों में इजाफा किया है। फेडरेशन ने यह इजाफा बढ़ती इनपुट लागत के चलते किया है। दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें 14 मई से लागू होंगी। बता दें, इससे पहले पिछली बार कीमतों में बढ़ोतरी 1 मई 2025 को की गई थी।

अमूल के साथ ही मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफा किया है। मदर डेयरी ने भी दो रुपये प्रति लीटर कीमत बढ़ाई है। मदर डेयरी ने भी इस फैसले के पीछे लागत की बढ़ती कीमत को ही बताया है।

क्यों हुआ इजाफा ?

यह बढ़ोतरी अमूल ताजा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल और अन्य प्रमुख वैरिएंट्स पर लागू होगी। अमूल ने बताया कि मई 2025 के बाद पहली बार दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी औसतन 2 .5 से 3 .5 प्रतिशत के बीच है, जो सामान्य खाद्य महंगाई दर से कम है। फेडरेशन ने कहा कि दूध उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है। पशु आहार, दूध पैकेजिंग फिल्म और ईंधन की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान काफी वृद्धि हुई है।

दूध की नई रेट

गुजरात (अहमदाबाद, सौराष्ट्र और कच्छ) में अमूल ताजा 500 मिली पैक अब 28 रुपए की जगह 29 रुपए में मिलेगा, जबकि 1 लीटर पैक 55 रुपए से बढ़कर 57 रुपए हो जाएगा। अमूल गाय दूध 500 मिली पैक की कीमत 29 रुपए से बढ़कर 30 रुपए कर दी गई है। अमूल शक्ति 500 मिली पैक अब 31 रुपए की जगह 32 रुपए में मिलेगा। अमूल टी स्पेशल 1 लीटर पैक की कीमत 63 रुपए से बढ़ाकर 66 रुपए कर दी गई है। अमूल गोल्ड 500 मिली पैक अब 34 रुपए की जगह 35 रुपए में मिलेगा। वहीं, अमूल भैंस दूध 500 मिली पैक की कीमत 37 रुपए से बढ़ाकर 39 रुपए कर दी गई है।

दिल्ली-NCR में तेज हवा के साथ ओले और भीषण बारिश

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को दिनभर गर्मी के बाद शाम को तेज बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में तेज हवा और ओलों के साथ बारिश हुई। जिसके बाद शहर का पारा गिर गया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवा के आसार जताए हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी। वहीं, अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होगा और उसके बाद 1-2C की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही धूल भरी आंधी की संभावना को देखते हुए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छिटपुट बादलों की आवाजाही की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों का मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में कुछ अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1C की हल्की वृद्धि हुई, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

यूपी में आंधी-तूफान से 62 लोगों की मौत

कई जिलों में बिजली व्यवस्था ठप

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी-पानी की चपेट में आने से अलग-अलग जिलों में 62 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। मरने वालों में भदोही में 11, मिर्जापुर में 6, सीतापुर में 2, कानपुर मंडल में 14, प्रयागराज में 9, प्रतापगढ़ में 4, रायबरेली में 2, संभल में दो और बरेली में 14 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिला अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कई जिलों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

नागरिकता कानून में हुआ बड़ा बदलाव, अब बच्चों के पास नहीं रहेंगे दो देशों के पासपोर्ट!

आर.एस.नेटवर्क। संवाददाता

नई दिल्ली। भारत सरकार ने नागरिकता और पासपोर्ट नियमों में आमूल-चूल बदलाव कर दिया है। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा गुरुवार को नोटिफाई किए गए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 के तहत अब नाबालिग बच्चों के लिए दोहरी नागरिकता रखना नामुमकिन होगा। सरकार ने इन नियमों को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है।

एक बच्चा, एक पासपोर्ट: दोहरी नागरिकता खत्म

नए नियमों के अनुसार, कोई भी नाबालिग बच्चा एक साथ भारतीय पासपोर्ट और किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता से जुड़े विवादों को खत्म करने और सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रावधान जोड़ा गया है। अब विदेश में पैदा हुए बच्चों का पंजीकरण कराते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास केवल एक ही देश की नागरिकता हो।

अब पूरी तरह डिजिटल होगा OCI कार्ड (e-OCI)

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पेपरलेस बना दिया गया है। अब ओसीआई कार्ड के लिए ऑफलाइन या मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सारा काम ociservices.gov.in पोर्टल के जरिए होगा। सरकार अब फिजिकल कार्ड के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई (e-OCI) भी जारी करेगी। पुराने इन डुप्लीकेट (दो प्रतियों में) डॉक्यूमेंट जमा करने का झमेला अब खत्म हो गया है।

OCI कार्ड सरेंडर करना हुआ अनिवार्य

अगर कोई व्यक्ति अपनी ओसीआई नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो उसे अपना फिजिकल कार्ड नजदीकी भारतीय मिशन या FRRO ऑफिस में जमा करना होगा। अगर सरकार किसी का ओसीआई स्टेटस रद्द करती है और व्यक्ति कार्ड वापस नहीं करता, तो भी डिजिटल रिकॉर्ड में उसे तुरंत रद्द (Cancel) मान लिया जाएगा।

एयरपोर्ट पर नहीं लगेगी लंबी लाइनें!

नए कानून का सबसे बड़ा फायदा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को मिलेगा। ओसीआई रजिस्ट्रेशन के समय लिए गए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग अब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाएगा। डेटा शेयरिंग के लिए आवेदकों की सहमति ली जाएगी, जिससे भविष्य में 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम' के तहत यात्रियों को बिना किसी रुकावट के एंट्री मिल सकेगी।

सुनवाई का मिलेगा पूरा मौका

अगर किसी का ओसीआई या नागरिकता आवेदन खारिज हो जाता है, तो उसे चुनौती देने के लिए एक नया अपील सिस्टम बनाया गया है। अब मामले की सुनवाई उस अधिकारी से एक रैंक सीनियर अधिकारी करेगा, जिसने फैसला सुनाया था।

अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत

लखनऊ। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लखनऊ सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अभी तक मौत के कारणों की कोई जानकारी नहीं आई है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार पर बड़ा संकट आ गया है। उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव हैं और वह भाजपा की नेता हैं। प्रतीक मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे हैं। बीते दिनों प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा के बीच खटपट की खबरें आई थीं। उनको बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल में लाया गया लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। अभी तक आधिकारिक तौर पर मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि प्रतीक यादव की मौत अननेचुरल है। उनकी ऊंगलियों के नाखुन नीले पड़ गए थे। इस कारण शक और गहरा गया है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है।

सस्पेक्टेड प्वाइजनिंग का मामला?

लेकिन, सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जीपी गुप्ता ने कहा कि सस्पेक्टेड प्वाइजनिंग का मामला हो सकता है। अब यह प्वाइजनिंग किस कारण हुआ, क्या उसको फुड प्वाइजनिंग हुआ या फिर उन्होंने किसी चीज का सेवन किया। ये सभी बातें जांच का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक वह अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में पड़े थे। पोस्टमार्टम के बाद सिविल अस्पताल से शव को घर ले जाया जाएगा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव का रिश्ता बहुत अच्छा था।

खून का थक्का बना मौत का कारण

रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का जमा हुआ था। शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में खून का थक्का गया। इसके बाद लंग्स में इंफेक्शन हुआ और कार्डिएक अरेस्ट से मौत हुई। विसरा रिपोर्ट के बाद और चीजें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने की वजह से दिल और सांस लेने की प्रक्रिया अचानक बंद हो गई, जिससे मौत हुई। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए दिल और फेफड़ों से जुड़े कुछ नमूनों को सुरक्षित रखा है।

पीएम मोदी के काफिले में 50% कटौती

गृह और रक्षा मंत्रियों ने भी कम की गाड़ियां

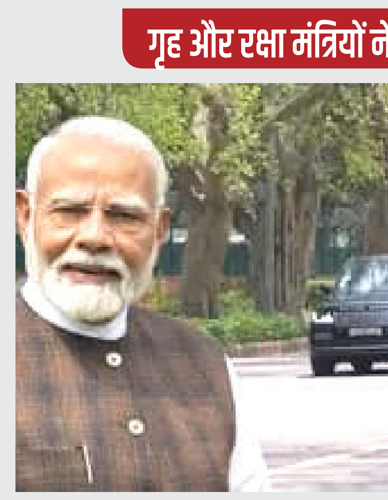

सरकारी खर्च में कटौती नहीं उन्हें तर्कसंगत बनाना

एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील को खर्च में कटौती से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग तक सीमित है। खर्च में कटौती का आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है।

उनके अनुसार संकट के समय सरकारी खर्चे में कटौती का सामान्य तरीका पूंजीगत, सबसिडी और कल्याणकारी योजनाओं के खर्चे में कटौती से होता है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए ईंधन की बचत की अपील का असर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक पूरे देश में दिखने लगा है।

खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में 50 फीसद की कटौती के बाद गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के काफिले की गाड़ियों में कटौती की गई।

इसके अलावा दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई राज्यपालों ने भी इसी तरह गाड़ियों की संख्या में कटौती की घोषणा की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा में संभाल रहे एसपीजी के अनुसार "ब्लू बुक" में दर्ज सुरक्षा मानकों से समझौता किये बिना सुरक्षा काफिले को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।

'ब्लू बुक' के निर्देशों का पालन

"ब्लू बुक" में वीवीआइपी की सुरक्षा के लिए लिखित विस्तृत निर्देश होते हैं, जिनका अक्षरशः पालन सुरक्षा में लगी एजेंसी को करना पड़ता है। इसके साथ ही सुरक्षा काफिले में ईवी गाड़ियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसके लिए नई ईवी गाड़ियों खरीद नहीं होगी।

सरकार की कोशिश आयातित तेल पर निर्भरता और पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोलियम बढ़ी कीमतों को देखते हुए इसके उपयोग को तर्कसंगत बना आयात बिल नियंत्रित करना है। इससे सरकार के खर्चे में कमी भी आएगी।

कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह जारी रहेगी

विकास की गति को बरकरार रखने के लिए पूंजीगत खर्च के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाएं भी पहले की तरह जारी रहेगी। सिर्फ खर्च को तर्कसंगत बनाकर सरकारी खजाने पर आए अतिरिक्त बोझ को कम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की अपील विदेश से आयातित सामानों और विदेशी मुद्रा से जुड़े सेवाओं पर गैरजरूरी निर्भरता कम करने को लेकर है।

रविवार को हैदराबाद से प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्पष्ट असर बुधवार को कैबिनेट की बैठक के पहले देखने को मिला। जहां प्रधानमंत्री के काफिले में दर्जन भर से अधिक गाड़ियों की जगह सिर्फ दो गाड़ियां देखने मिली। लेकिन इसकी शुरूआत हैदराबाद से ही हो चुकी थी। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को असम में हिमंत विश्व सरमा के शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों में कटौती की गई थी।

Crude Oil की बढ़ती कीमतों पर RBI का अलर्ट, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत को अंततः पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति, ईंधन आयात और समग्र अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रही हैं। स्विट्जरलैंड में स्विस नेशनल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए, मल्होत्रा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागत से अनिश्चित काल तक बचा नहीं पाएगी। मल्होत्रा ने कहा कि अगर यह सिलसिला लंबे समय तक जारी रहता है, तो सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने में बस कुछ ही समय लगेगा। भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होने के बाद से बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। इस महत्वपूर्ण जल परिवहन मार्ग पर व्यवधान ने आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों, मुद्रास्फीति और भारत के बढ़ते ऊर्जा आयात बिल को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की आवश्यकताओं का आयात करता है, जिससे अर्थव्यवस्था वैश्विक तेल कीमतों में निरंतर वृद्धि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाती है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें परिवहन और विनिर्माण लागत बढ़ाती हैं, रुपये पर दबाव डालती हैं और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में योगदान करती हैं। फिलहाल, केंद्र सरकार और सरकारी तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा वहन कर रही हैं।

संपादकीय

NEET पेपर लीक...

अभी 3 मई की रात को करीब 23 लाख बच्चों ने महीनों बाद पहली बार सुकून की सांस ली थी। किसी ने मां से कहा कि मम्मी पेपर अच्छा हो गया। किसी ने पापा से कहा कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उन लाखों बच्चों को लग रहा था कि उनकी जिंदगी जो है वह बदलने वाली है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये खबर आती है जिसने उनकी दुनिया को हिला कर दिया है। पेपर लीक की शिकायतों के बाद नीट एग्ज़ाम रद्द हो गया है। 3 मई को ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका एग्ज़ाम अब फिर से होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक इस देश में लाखों बच्चों से कहा जाएगा कि बच्चे तुम ना फिर से तैयारी कर लो। एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। आखिर कब तक इस देश में बच्चे पेपर लीक, करप्शन और सिस्टम की नाकामियों का बोझ उठाते रहेंगे? एक बच्चा है जिसकी दुनिया स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और चार दीवारी के एक छोटे से कमरे तक सिमट चुकी थी। जिसने महीनों से सालों से अपने दोस्तों से दूरियां बनाई थी। वो त्यौहार पर अपने घर नहीं गया। उसने मोबाइल फोन छोड़ दिया। उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। आईपीएल देखना छोड़ दिया। दोस्तों के साथ मौज मस्ती, बाहर घूमना फिरना छोड़ दिया। क्योंकि उसे यह बताया गया था उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स के थ्रू कि बच्चे मेहनत कर लो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अचानक सिस्टम एक दिन कहता है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। उसी पल उन लाखों बच्चों को ऐसा लगता है जैसे उनकी मेहनत नहीं उनके भरोसे को खत्म कर दिया गया हो। उनकी जिंदगी उन्हें करियर से खिलवाड़ कर दिया गया हो।

2024 में लीक स्थानीय (पटना और गोधरा) था, जबकि 2026 में डिजिटल प्रसार के कारण यह राष्ट्रव्यापी हो गया।

तब बचाव की नीति थी, 2026 में जीरो टॉलरेंस के तहत तुरंत फैसला।

अब सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू है। इसमें सजा जुर्माना ज्यादा है।

दूसरे देशों में कैसे कानून हैं?

चीनः नकल या पेपर लीक पर 7 साल तक वेल। इसे 'देशद्रोह जैस्स मानते हैं।

बांगलादेश, द. कोरिया पेपर लीक पर 10 साल तक की बेल और आजीवन ब्लैकलिस्ट करने का सख्त नियम।

अल्जीरियाः परीक्षा के दौरान देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन व जेल का प्रावधान।

अभ्यर्थियों पर क्या असर होगा?

दोबारा परीक्षा की अनिश्चितता, तैयारी की लय टूटना बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ।

पीएम मोदी के राष्ट्रहित के आह्वान में भी राजनीति क्यों?

"इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ता है।

आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं ने मानव सभ्यता को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। खाड़ी देशों में लंबे समय से चल रहे संघर्ष और युद्ध की विभीषिका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे तक प्रभावित किया है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं का बाधित होना, डॉलर के मुकाबले विभिन्न देशों की मुद्राओं का कमजोर होना और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न असंतुलन ने लगभग हर राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इन परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है और सोने का भी विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन के संयमित उपयोग और सोने की खरीद को सीमित करने का आह्वान केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया दूरदर्शी चिंतन है। दुर्भाग्य यह है कि मोदी की मितव्ययिता की अपील पर पूरे देश को एकजुट होकर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, उस विषय को भी राजनीतिक विवाद का हथियार बना दिया गया। कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की इस अपील को जनता में भय फैलाने वाला कदम बताया, तो कुछ ने इसे सरकार की विफलताओं को छिपाने का प्रयास कहा। जबकि वस्तुतः यह अपील राष्ट्र को भविष्य की संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत करने और समय रहते आत्मानुशासन अपनाने का संदेश है। यह राजनीति का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी का प्रश्न है। जब विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र आर्थिक संकटों से जूझ रहे हों, तब भारत के प्रधानमंत्री यदि नागरिकों को संयम एवं मितव्ययिता का सूत्र देते हैं तो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह पहला अवसर नहीं है, जब प्रधानमंत्री ने देश की तरक्की को बनाए रखने की सामूहिक चिन्ता करते हुए मितव्ययिता एवं संयम की अपील की हो।

भारत की संस्कृति मूलतः संयम प्रधान रही है। भारतीय जीवन-दर्शन में संयम को केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। हमारे ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने सदैव आवश्यकता और विलासिता के बीच अंतर

करना सिखाया। महावीर, बुद्ध, गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने त्याग और संयम को ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भारतीय संस्कृति कहती है कि जितना आवश्यक हो उतना ही उपभोग करो, क्योंकि असीमित उपभोग अंततः संकट को जन्म देता है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों तक टिकाऊ और संतुलित बनी रही। आज जब पूरी दुनिया उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम भुगत रही है, तब भारत की यही संयम आधारित संस्कृति समाधान का मार्ग दिखा सकती है। सोने के प्रति भारतीय समाज का आकर्षण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरा रहा है। विवाह, पारिवारिक उत्सव, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक प्रतिष्ठा में सोने का विशेष स्थान है। लेकिन यह भी एक कठोर सत्य है कि भारत का अधिकांश सोना आयातित होता है। हर वर्ष अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सोने के आयात पर खर्च होता है। यह सोना उत्पादन या औद्योगिक विकास में उपयोग होने के बजाय घरों और लॉकरों में बंद होकर निष्क्रिय पड़ा रहता है। ऐसे समय में जब विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा हो और रुपये की कीमत लगातार गिर रही हो, तब सोने की खरीद में संयम बरतने की अपील आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। यह किसी की परंपराओं के विरोध में नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती के पक्ष में उठाया गया कदम है।

इसी प्रकार ईंधन के उपयोग में संयम भी समय की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयातित तेल पर निर्भर है। खाड़ी देशों में युद्ध और अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, परिवहन, उद्योग और महंगाई पर पड़ता है। यदि नागरिक ईंधन के अनावश्यक उपयोग को सीमित करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, ऊर्जा बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। संयम का अर्थ केवल त्याग नहीं होता, बल्कि दूरदर्शिता और जिम्मेदारी भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील इसी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती या प्रतिबंध की बात नहीं की, बल्कि नागरिकों से स्वैच्छिक सहयोग की अपेक्षा की। यह लोकतांत्रिक नेतृत्व की पहचान है।

एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का कर्तव्य केवल संकट आने पर कदम उठाना नहीं होता, बल्कि संकट के संकेतों को पहचानकर समय रहते जनता को तैयार करना भी होता है। आज जब दुनिया के कई देशों में आर्थिक अस्थिरता के कारण भारी महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव देखने को मिल रहे हैं, तब भारत अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में है। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति का परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी संकटों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। महामारी से लेकर युद्धजनित परिस्थितियों तक भारत सरकार ने लगातार राहत योजनाएं चलाईं, गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, किसानों और मध्यम वर्ग को विभिन्न प्रकार की सहायता दी तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए। वैश्विक मंदी और युद्ध के वातावरण में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देशहित के ऐसे विषयों पर भी कुछ राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन हर विषय को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू में तौलना राष्ट्रहित के विरुद्ध है। यदि प्रधानमंत्री जनता से संयम की अपील करते हैं तो विपक्ष को चाहिए कि वह भी जनता को जागरूक करे, न कि भय और भ्रम का वातावरण बनाए। राजनीति तब तक स्वस्थ मानी जाती है जब तक वह राष्ट्रहित से जुड़ी रहे। लेकिन जब राजनीति केवल विरोध के लिए विरोध करने लगे और राष्ट्रीय संकटों को भी अवसर की तरह देखने लगे, तब वह लोकतंत्र को कमजोर करती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरा देश एक परिवार की तरह सोचते हुए राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माने। संकट के समय संयम, अनुशासन और सहयोग ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भारत ने इतिहास में अनेक बार यह सिद्ध किया है कि जब भी राष्ट्र पर संकट आया, भारतीय समाज ने अद्भुत त्याग और एकता का परिचय दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर युद्धकाल तक, भारतीय जनता ने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को महत्व दिया है। आज फिर वही समय है जब हमें समझना होगा कि अनावश्यक उपभोग, दिखावे की प्रवृत्ति और अंधाधुंध विलासिता अंततः देश की आर्थिक मजबूती को कमजोर करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। यह केवल सोना न खरीदने या ईंधन बचाने का संदेश नहीं, बल्कि आत्मसंयम, आत्मअनुशासन और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का संदेश है। भारतीय संस्कृति का मूल स्वर भी यही रहा है कि व्यक्ति अपने आचरण से समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाए। यदि हम संयम को जीवन का हिस्सा बना लें तो अनेक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान स्वतः संभव हो सकता है। आज दुनिया जिस अनिश्चितता और संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें भारत अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसका श्रेय देश की जनता की सामर्थ्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी जाता है। ऐसे समय में आवश्यकता राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सकारात्मक सोच की है। संयम केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का आधार है।

- ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

ईरानी विमानों को अपने यहाँ छिपा कर पाकिस्तान ने उतार दिया 1971 का कर्ज

1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारतीय हमलों से बचाने के लिए ईरान ने पाकिस्तानी सैन्य विमानों और संसाधनों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पांच दशक बाद पाकिस्तान उसी एहसान का बदला चुकाता दिखाई देगा। अब आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय तनाव के बीच पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने सैन्य ठिकानों पर सुरक्षित शरण दी। इस तरह इस्लामाबाद ने तेहरान का पुराना कर्ज तो उतार दिया है लेकिन अब वह खुद संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की जटिल कूटनीतिक राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि इस तरह के दावे वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि नूर खान वायुसेना अड्डा राजधानी के अत्यंत व्यस्त और आबादी वाले हिस्से में स्थित है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां किसी भी बड़े सैन्य बेडे या विमानों को छिपाकर रखना संभव ही नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने भी अब तक सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान पर कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार ईरान ने संभावित खतरे को देखते हुए अपने कुछ नागरिक विमानों को पड़ोसी अफगानिस्तान की ओर भेजा। अफगान नागरिक उड्डयन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महान एयर का एक विमान संघर्ष तेज होने से पहले काबुल पहुंचा था और बाद में सुरक्षा कारणों से उसे हेरात स्थानांतरित कर दिया गया। बताया गया कि अफगान क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमलों की खबरों के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि काबुल हवाई अड्डा भी संभावित निशाना बन सकता है।

इन घटनाओं ने दक्षिण एशिया के जानकारों को 1971 के दौर की याद दिला दी है। उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व वाला ईरान पाकिस्तान का प्रमुख समर्थक बनकर सामने आया था। तेहरान ने इस्लामाबाद को हेलिकाप्टर, ईंधन, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के कलपुर्जे उपलब्ध कराए थे। कई रिपोर्टों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पाकिस्तान के कुछ सैन्य विमानों ने ईरानी वायुसेना अड्डों पर शरण ली थी।

बाद में सार्वजनिक हुए अमेरिकी दस्तावेजों से पता चला था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन प्रशासन ने पर्दे के पीछे ईरान को पाकिस्तान की सहायता के लिए प्रोत्साहित किया था। उस दौर में अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान को कमजोर होने से बचाना चाहते थे। शीत युद्ध के समय ईरान और पाकिस्तान दोनों सोवियत विरोधी सैन्य गठबंधन सेन्टो के सदस्य थे और निक्सन प्रशासन इन्हें क्षेत्र में सोवियत प्रभाव को रोकने वाले महत्वपूर्ण साझेदार मानता था।

पांच दशक बाद वैश्विक राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। आज ईरान अमेरिका का प्रमुख पश्चिम एशियाई प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, जबकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में चीन का सबसे करीबी सुरक्षा सहयोगी बन चुका है। चीन ने हाल के समय में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराने में पाकिस्तान की भूमिका की सार्वजनिक सराहना भी की है। इस बदलती परिस्थिति में पाकिस्तान का संतुलन साधना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है।

पाकिस्तान एक ओर चीनी सैन्य उपकरणों पर अत्यधिक निर्भर है। रिपोर्टों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के प्रमुख हथियार आयात का लगभग अस्सी प्रतिशत हिस्सा चीन से आया। वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद अमेरिका के साथ अपने सैन्य और खुफिया संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है, जो बराक ओबामा प्रशासन के दौरान काफी कमजोर पड़ गए थे। पाकिस्तानी अधिकारी लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि तेहरान के साथ उनके संबंध किसी गुप्त सैन्य सहयोग की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रचनात्मक कूटनीति का हिस्सा हैं। पाकिस्तान समय समय पर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी करता रहा है। उसका दावा है कि दोनों देशों के साथ कार्यकारी संबंध बनाए रखने की उसकी क्षमता क्षेत्रीय तनाव कम करने में सहायक हो सकती है।

इसके बावजूद अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक प्रभावशाली हिस्से में पाकिस्तान को लेकर संदेह अब भी गहराई से मौजूद है। अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी की स्मृति आज भी अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर भारी पड़ती है। अमेरिकी अधिकारी और सांसद लंबे समय से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के कुछ तत्वों पर इस्लामी उग्रवादी संगठनों के साथ चयनात्मक संबंध रखने के आरोप लगाते रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों को लगातार नकारता आया है।

ताजा आरोपों ने अमेरिकी संसद में भी नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान द्वारा ईरान को सैन्य सहायता या शरण देने की खबरें सही साबित होती हैं, तो अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ के रूप में इस्लामाबाद की भूमिका का पूरी तरह पुनर्मूल्यांकन करना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति में पुराने रिश्ते, सामरिक हित और बदलते वैश्विक गठबंधन आज भी गहराई से प्रभाव डाल रहे हैं।

बहरहाल, विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान पर आंख मूंदकर भरोसा करना अमेरिका सहित कई देशों के लिए पहले भी भारी पड़ चुका है। हाल के वर्षों में अमेरिकी रणनीतिक और सुरक्षा रिपोर्टों में भी यह संकेत दिया गया था कि पाकिस्तान की नीतियां भविष्य में अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष चुनौती बन सकती हैं। कुछ विश्लेषणों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया है जिनके फैसले क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकते हैं और अमेरिकी हितों के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। यही कारण है कि वाशिंगटन में यह राय मजबूत होती जा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सामरिक या कूटनीतिक साझेदारी में अमेरिका को अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी।

धर्म

17 मई से 15 जून तक रहेगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये काम

अधिकमास यानी 13 महीनों का साल। सनातन धर्म में अधिकमास का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। अधिकमास को भगवान विष्णु को समर्पित महीना माना जाता है। हिंदू धर्म में हर तीसरे साल में एक अधिकमास पड़ता है। इसको पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है। इस माह में किया गया भगवान विष्णु का व्रत और पूजन बहुत अधिक पुण्य देता है। मान्यता है कि इस माह में किया गया दान भी विशेष फल देता है।

इस साल 17 मई से अधिकमास की शुरुआत होने जा रही है। ये माह 15 जून तक रहेगा। जहां इस माह में की गई पूजा-पाठ और व्रत विशेष माने जाते हैं, वहीं अधिकमास में कुछ कार्यों को करने की मनाही भी होती है। इस दौरान जो कोई भी ये कार्य करता है उन्हें अशुभ फल प्राप्त होते हैं, तो आइए जानते हैं अधिकमास में न किए जाने वाले कामों के बारे में।

अधिकमास में न करें ये काम

अधिकमास में मांगलिक कार्यों को करने से मना किया जाता है, इसलिए इस दौरान विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार और सगाई जैसे मांगलिक काम भूलकर भी न करें। मान्यता है कि इस दौरान ये सभी मांगलिक काम शुभ फल नहीं देते।

अगर आप नए कारोबार को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो अधिकमास के समापन के बाद करें। अधिकमास में भूलकर भी नया कारोबार न शुरू करें। इस दौरान शुरू किये गये काम में सफलता से ज्यादा असफलता की संभावना रहती है।

अधिकमास में नए घर की नींव रखना या नए घर में प्रवेश करना शुभ नहीं होता। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नए घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस दौरान ये काम न करें।

अधिकमास में मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन न करें। इस महीने में सात्विक जीवन जीने की सलाह दी जाती है।

अधिकमास में जमीन, सोना, नई गाड़ी या अन्य महंगी चीजें न खरीदें। इस मास में ये चीजें खरीदना अशुभ होता है। इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।

अधिकमास में अधिक गुस्सा करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अलावा किसी का अपमान भी नहीं करें।

बदलते मौसम में बुज़ुर्गों को बीमारियों का खतरा, इस तरह रखें खास ध्यान

देश के कई राज्यों में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। बदलते मौसम का असर बुजुर्गों की सेहत पर जल्दी पड़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की इम्यूनिटी क्षमता कमजोर होने लगती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। जिन बुजुर्गों को पहले से डायबिटीज, हाई बीपी, अस्थमा या हृदय रोग जैसी समस्याएं हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

तापमान में अचानक बदलाव शरीर के लिए चुनौती बन सकता है। कई बार शरीर को नए मौसम के अनुसार ढलने में समय लगता है, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बुजुर्गों में एनर्जी स्तर कम होना, भूख में कमी और संक्रमण से लड़ने की क्षमता घटने जैसी स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बदलते मौसम में बुजुर्गों की सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए और किन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ। सुभाष गिरि बताते हैं कि बदलते मौसम में बुजुर्गों को सर्दी-खांसी, बुखार, वायरल संक्रमण, सांस की तकलीफ और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों को अस्थमा, सीओपीडी, डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी पुरानी बीमारियां हैं, उनमें लक्षण और अधिक गंभीर हो सकते हैं।

इसके अलावा, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव, कमजोरी, डिहाइड्रेशन और भूख कम लगने जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ बुजुर्गों में शरीर दर्द, थकान और नींद की कमी की शिकायत भी बढ़ सकती है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है, इसलिए उनकी सेहत पर लगातार नजर रखना जरूरी है।

बुजुर्गों की देखभाल के लिए किन बातों का ध्यान रखें?

बुजुर्गों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और पौष्टिक भोजन दें। उनके आहार में फल, सब्जियां, प्रोटीन और हल्का भोजन शामिल करें। नियमित दवाएं समय पर देना और पर्याप्त आराम करवाना भी जरूरी है। घर का तापमान संतुलित रखें और बहुत ज्यादा गर्म या ठंडी हवा से बचाएं। संक्रमण से बचाव के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखें और हाथ धोने की आदत बनाए रखें। अगर कोई पुरानी बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच और फॉलो-अप करवाते रहें।

किन लक्षणों में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए?

अगर तेज बुखार, लगातार खांसी, सांस फूलना, सीने में दर्द, अत्यधिक कमजोरी या भ्रम की स्थिति दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये लक्षण गंभीर संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा, भूख बिल्कुल कम हो जाना, पेशाब में कमी, चक्कर आना, अचानक सूजन बढ़ना या व्यक्ति का सामान्य से अधिक सुस्त दिखना भी चिंता का कारण हो सकता है। समय पर इलाज से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह को पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरावणे ने किया सम्मानित

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

मुंबई। मुंबई में आयोजित टीवी पत्रकारिता सम्मान समारोह में वरिष्ठ टीवी जर्नलिस्ट तथा 'श्रेष्ठ भारत डिजिटल चैनल के एडिटर (स्पेशल प्रोजेक्ट) सुनील सिंह को इंफ्रास्ट्रक्चर की विशिष्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत के पूर्व थलसेना प्रमुख मनोज नरवणे के हाथों प्रदान किया गया।

मंगलवार शाम रविंद्र नाट्य मन्दिर, प्रभादेवी में आयोजित कार्यक्रम में टीवी पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में आशीष शेलार, प्रताप सरनाईक, आशीष जैसवाल तथा प्रसाद लाड सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

सुनिल सिंह ने देश की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर साहसिक और जमीनी रिपोर्टिंग की है। मिजोरम में पहली बार रेल पहुंचने के दौरान दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की उनकी रिपोर्टिंग विशेष रूप से सराही गई। उन्होंने यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में रेल पटरियां कैसे बिछाई गईं और परियोजना को कैसे पूरा किया गया।

इससे पहले गढ़चिरौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव, औद्योगिक विकास और नक्सलवाद की चुनौतियों पर उनकी रिपोर्टिंग को भी काफी प्रशंसा मिली थी, जिसके लिए उन्हें गौतम प्रतिष्ठान द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया था।

हाल ही में उन्होंने टाइगर वैली के नीचे बनने वाली विशाल सुरंगों और भारत के सबसे ऊंचे केबल स्टेड ब्रिज पर पहुंचकर भी विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग की। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर उनकी गहन रिपोर्टिंग ने उन्हें इस क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाई है।

नेशनल लोक अदालत में ठाणे जिले का राज्य में दबदबा

29 हजार केस निपटाए, लगातार पांचवीं बार पहला स्थान हासिल किया

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणे।नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार, साल की दूसरी 'नेशनल लोक अदालत' शनिवार, 9 मई, 2026 को ठाणे जिले में लगी। ठाणे जिले ने इस लोक अदालत में पेंडिंग केस निपटाने में अपना दबदबा बनाए रखा है और लगातार पांचवीं बार राज्य में पहला स्थान हासिल किया है।चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीनिवास बी. अग्रवाल के मार्गदर्शन में, ठाणे और पालघर जिले की सभी अदालतों में कुल 110 पैनल के ज़रिए इस लोक अदालत की कार्रवाई की गई।इस लोक अदालत में कुल 29 हजार 392 केस निपटाए गए। इसमें 12,186 लंबित मामले और 17,206 प्री-लिटिगेशन मामले शामिल हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से 63,42,52,648 रुपये का रिकॉर्ड समझौता किया गया है।इस बार 5, 10, 20 और यहां तक कि 30 साल से लंबित कुल 567 पुराने मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया।मोटर दुर्घटना बीमा दावेः जिले में 120 मामलों में 15,64,000 रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया। एक विशेष मामले में, मृतक के उत्तराधिकारियों को 87 लाख रुपये का मुआवजा चेक प्रदान किया गया।पारिवारिक सुलहः पारिवारिक विवादों के 30 मामलों में सफल समझौता किया गया, जिनमें से 7 मामलों में पति-पत्नी ने फिर से साथ रहने का फैसला किया।चेक अनादर और अन्यः चेक अनादर (एन.आई. एक्ट 138) के 1,146 मामलों का निपटारा किया गया और रु। 19 करोड़ 58 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही, ट्रांसपोर्ट बिल के 6,983 मामलों का भी निपटारा किया गया।

डॉ.शर्मिन डिंगा ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणे। मुंब्रा पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी और ठाणे नगर निगम अस्पताल में कार्यरत डॉ. शर्मिंग डिंगा (33) ने बुधवार की सुबह लगभग 11:15 बजे अज्ञात कारणों से अपने आवास की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली।

मुंब्रा स्थित मुंबई-पुणे रोड, भारत गियर, दोस्ती प्लैनेट, 1801 की निवासी डॉ. शर्मिन डिंगा के तीन बच्चे हैं और उनके पति विदेश में कार्यरत हैं। मृतक के पिता शब्बीर डिंगा, जो ग्रेस स्क्वायर बिल्डिंग, ए5, कमरा नंबर 605 और 606 में रहते थे, ने अपने घर की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद, डॉ. डिंगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल भेज दिया गया है। मुंब्रा पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

बाइक पर आए हुए लुटेरों ने टेम्पो चालक को चाकू का इस्तेमाल करके लुट लिया

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणे। शिकायतकर्ता बालासाहेब पचपुंजे ने कलवा पुलिस स्टेशन में दो अज्ञात लुटेरों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कराया है, क्योंकि लुटेरों ने उन्हें नकदी और मोबाइल फोन लूटने की धमकी देकर उनका दोपहिया वाहन लूट लिया था।

शिकायतकर्ता बालासाहेब मधुकर पचपुंजे (31), निवासी भिवंडी, रविवार शाम लगभग 7-10 बजे, टाटा कंपनी की इंट्राटा टेम्पो से गणेश घाट रेतीबंदर खारेगांव कलवा से डोंबावली की ओर जा रहे थे, तभी यूनिकॉर्न बाइक पर सवार दो लोगों ने टेम्पो के सामने अपनी बाइक रोक दी। बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने बालासाहेब को पास में मौजूद चाकू से जान से मारने की धमकी दी और उनकी जेब से मोबाइल फोन और नकदी छीनकर बाइक पर फरार हो गया। इस मामले में दोनों के खिलाफ कलवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

सिंधुताई सपकाल आर्चरी सेंटर के 'पैडल कोर्ट' का परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शिलान्यास किया

यह पहल युवा सेना के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक के कॉन्सेप्ट पर लागू की जा रही है

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणे। ओवाला-माजीवाड़ा विधानसभा सीट के पोखरण रोड नंबर 2 में सिंधुताई सपकाल आर्चरी सेंटर में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट "पैडल कोर्ट" बनाने का शिलान्यास आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के शुभ हाथों से हुआ।

इस पैडल कोर्ट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट युवा सेना के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक का है, और यह ज़रूरी पहल युवाओं को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्पोर्ट्स फैसिलिटी देने के मकसद से लागू की जा रही है। इस मौके पर ठाणे शहर की मेयर शर्मिला पिंपलोलकर, लोकल कॉर्पोरेटर परिषा सरनाईक, जयश्री डेविड, सुलेखा चव्हाण, कॉर्पोरेटर सीताराम राणे, साथ ही डिप्टी कमिश्नर मीनल पलांडे, साथ ही आम लोग, खेल के शौकीन, युवा खिलाड़ी और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी मौजूद थे।

प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस पहल के पीछे मुख्य मकसद मॉडर्न स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना और युवाओं को अच्छी सुविधाएं देना है। इस मौके पर बोलते हुए, मंत्री सरनाईक ने कहा कि "पैडल एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और यह टेनिस और स्क्वैश का अगला खेल है। इसे एक संगम माना जाता है। यह खेल सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी और दिलचस्प है। यह पैडल कोर्ट ठाणे के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं देने और भविष्य में नेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

"सिंधुताई सपकाल आर्चरी सेंटर में बनने वाला यह कोर्ट मॉडर्न टेक्निकल सुविधाओं से लैस होगा और युवाओं को रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देगा। मौजूद लोगों ने कहा कि इस पहल से इलाके में स्पोर्ट्स कल्चर को एक नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर यह भी कहा गया कि यह काम ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़रिए किया जाएगा और काम जल्द से जल्द पूरा करके खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कर्मचारियों के पेंडिंग मामलों पर प्रशासन तुरंत एक्शन ले: मेयर शर्मिला पिंपलोलकर

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणे। मनपा में काम करने वाले परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर मेयर शर्मिला पिंपलोलकर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सर्विस, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, आश्रित प्रगति योजना, ग्रेच्युटी, मेडिकल सुविधाओं और अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की पेंडिंग मांगों से जुड़े मामलों पर डिटेल में चर्चा हुई और मेयर ने प्रशासन को कर्मचारियों के मामलों को तुरंत हल करने का निर्देश दिया।

मेयर का पद संभालने के बाद मेयर शर्मिला पिंपलोलकर ने मनपा के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके पेंडिंग मामलों के बारे में अपनी बातें रखीं। इन सभी बातों पर प्रशासन के साथ चर्चा करने के लिए मंगलवार (12 मई) को स्वर्गीय अरविंद पेंडसे हॉल में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में मनपा कमिश्नर सौरभ राव, डिप्टी मेयर कृष्णा पाटिल, हाउस के लीडर हनमंत जगदाले, अपोज़िशन के लीडर अशरफ शानू पठान, शिवसेना ग्रुप लीडर पवन कदम, एडिशनल कमिश्नर 1 संदीप मालवी, एडिशनल कमिश्नर 2 प्रशांत रोडे, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोदापुरे, मनीष जोशी, मधुकर बोडकरे के साथ एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और सभी डिपार्टमेंट हेड मौजूद थे। इस मीटिंग में फायर डिपार्टमेंट में कर्मचारियों का प्रमोशन, खाली पोस्ट भरना, क्लर्क और टाइपिस्ट के पोस्ट पर प्रमोशन, अस्वास्थ प्रगति योजना, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय, सातवां पे कमीशन, रिटायर्ड कर्मचारियों का एरियर, मेडिकल ऑफिसर की सैलरी और अलग-अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई। साथ ही, जिन कर्मचारियों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्हें पर्सनली बुलाया गया और उनके सवालों पर चर्चा की गई। इस समय मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने निर्देश दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित मुद्दों का पॉजिटिव नज़रिए से अध्ययन करे और कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर तुरंत एक्शन ले। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि कर्मचारियों की समस्याओं को समझने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। कमिश्नर सौरभ राव ने कहा कि मेयर ने प्रशासन को सभी मुद्दों की स्टडी करने और स्टेप बाय स्टेप पॉज़िटिव फ़ैसले लेने का निर्देश दिया है और कर्मचारियों के पेंडिंग मुद्दों को लेकर प्रशासन सेंसिटिव तरीके से काम करेगा। इस मौके पर श्रमिक जनता संघ, म्युनिसिपल लेबर यूनियन, कामगार एकजुट संगठन, TMT एम्प्लॉई यूनियन, ठाणे मनपा प्राइमरी टीचर्स यूनियन, महाराष्ट्र स्टेट ग्रुप प्रमोटर और आशा वॉलंटियर्स एसोसिएशन,मनपा ट्रांसपोर्ट सर्विस एम्प्लॉई एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे।

परामर्श के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण, स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम घोषित

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणे। ठाणे, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों के सामान्य स्थानांतरणों के लिए परामर्श प्रक्रिया को गति देते हुए, एक अलग सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है, जिसमें इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अबितकर और राज्य मंत्री मेघना सकोरे-बोरदिकर के मार्गदर्शन में, इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और इसमें अधिक एकरूपता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, परामर्श के माध्यम से सामान्य स्थानांतरण करने की प्रक्रिया स्थापित की गई है। परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने आठों प्रशासनिक क्षेत्रों में सभी कार्यक्रम प्रमुखों के स्थानांतरणों के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, रिक्त पदों की सूची 6 मई, 2026 को प्रकाशित की गई थी। इसके बाद, स्थानांतरण के लिए पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची 8 मई, 2026 को प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त, फॉर्म 1 से 5 तैयार किए गए और 10 मई, 2026 को सिविल सेवा बोर्ड को प्रस्तुत किए गए। परामर्श के माध्यम से स्थानांतरणों के लिए अंतिम प्रस्ताव सिविल सेवा बोर्ड द्वारा 15 मई, 2026 तक आगे बढ़ाए जाने हैं। परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जारी होने वाले अंतिम स्थानांतरण आदेश, 31 मई को विभाग की वेबसाइट पर जारी किए जाने निर्धारित हैं। इस पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया की देखरेख के लिए, चार वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस नई नीति के तहत, स्थानांतरण करते समय सेवा की अवधि, प्राथमिकता की स्थिति, पसंद के विकल्प, प्रशासनिक आवश्यकताएं और दूरदराज के क्षेत्रों में दी गई सेवा जैसे कारकों को विशेष महत्व दिया गया है। मानवीय आधारों को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसमें दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, विधवाएं, पति-पत्नी के एकीकरण से जुड़े मामले और शैक्षिक आधार पर मांगे गए स्थानांतरण शामिल हैं। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रशासनिक और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा, और किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में योगदान मिलेगा। यह व्यापक स्थानांतरण नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी दृष्टिकोण को सुगम बनाएगी, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

ठाणे के शिवई नगर में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला

आत्महत्या की सूचना मिली...हत्या और फांसी का संदेह

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणे। ठाणे के वर्तकनगर पुलिस थाना क्षेत्र के शिवई नगर में एक 23 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। हालांकि, वर्तकनगर पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

मंगलवार तड़के करीब 8:26 बजे प्रवीण वानखेड़े (23 वर्ष) ने ठाणे (पश्चिम) के शिवई नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही वागले फायर स्टेशन, पश्ते सो. के स्टेशन ऑफिसर, वर्तकनगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, एक शव वाहन, दमकलकर्मी और एक आपातकालीन वाहन के साथ मौके पर पहुंचे।

दमकलकर्मियों की सहायता से शव को पेड़ से उतारा गया और वर्तकनगर पुलिस को सौंप दिया गया। शव को वर्तकनगर पुलिस की उपस्थिति में आगे की कार्रवाई के लिए शव वाहन से ठाणे के जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।

तळोजा जेल में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों की तलाश जारी

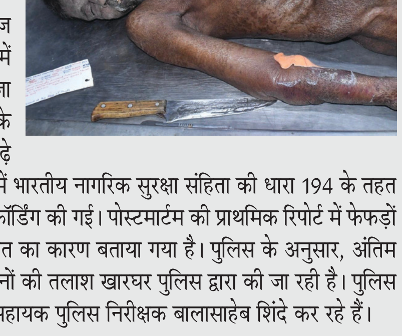

आर .एस. नेटवर्क। ठाणे संवाददाता

नवी मुंबई । तळोजा केंद्रीय कारागृह में बंद एक विचाराधीन कैदी की मुंबई के सर जे.जे. अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मण ढाकू वाघमारे (66 वर्ष, निवासी भिवंडी, ठाणे) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में खालापुर पुलिस थाने में दर्ज हत्या के मामले में वाघमारे को तळोजा जेल में न्यायबंदी के रूप में रखा गया था। उन्हें टीबी की बीमारी होने के कारण 12 मार्च 2026 को उपचार के लिए मुंबई के सर जे.जे. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 12 अप्रैल की सुबह करीब साढ़े आठ बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलने के बाद सर जे.जे. मार्ग पुलिस थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। कार्यकारी दंडाधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में फेफड़ों की बीमारी, पल्मोनरी कंसॉलिडेशन, फैटी लिवर तथा लंबे समय से चली आ रही किडनी की बीमारी को मौत का कारण बताया गया है। पुलिस के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के बाद जारी की जाएगी। इस बीच, मृत न्यायबंदी लक्ष्मण वाघमारे के परिजनों की तलाश खारघर पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि संबंधित परिजन तत्काल खारघर पुलिस थाने से संपर्क करें। मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक बालासाहेब शिंदे कर रहे हैं।

हिंदी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

हिंदी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहारः रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रा वाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001,
भ्र.ध्व . क्र.:9224733113
ईमेलः rastriyaswabhimaan@gmail.com

कापुरबावड़ी ट्रैफिक विभाग की शानदार कार्रवाई

बेलगांव से चोरी हुई KIA Seltos कार बरामद

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
ठाणे। कापुरबावड़ी ट्रैफिक विभाग ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए बेलगांव से चोरी हुई KIA कंपनी की Seltos कार को बरामद कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना फिल्मी अंदाज में कार का पीछा किया।

जानकारी के अनुसार, 10 मई 2026 को पुलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट और नियंत्रण कक्ष, यातायात विभाग ठाणे शहर के आदेश पर गोल्डन क्रॉस इलाके में ड्रंक एंड ड्राइव नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि चोरी की एक KIA कार (नंबर 22MC8122) नवी मुंबई सीमा से ठाणे शहर की ओर आ रही है। वाहन चोरी का होने के साथ चालक को हिरासत में लेने के निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही पीएसआई सागर सांगवे के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार विधाते, पुलिस शिपाई अश्रु हाके और रघुनाथ वळेकर ने गोल्डन क्रॉस, माजीवाड़ा इलाके में नाकाबंदी शुरू की। कुछ ही देर में बताई गई कार गोकुलनगर दिशा से आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने कार पुलिसकर्मियों की ओर मोड़ते हुए तेज रफ्तार में घोड़बंदर दिशा की ओर फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस शिपाई अश्रु हाके ने साहस दिखाते हुए कार का पैदल पीछा शुरू किया। बाद में उन्होंने रास्ते से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय की पल्सर बाइक रुकवाई और घटना की जानकारी देकर बाइक लेकर आरोपी का पीछा शुरू किया। पीछा करते समय आरोपी चालक कई बार कार को पुलिसकर्मी की ओर मोड़कर भागने का प्रयास करता रहा। इस दौरान आरोपी ने रास्ते में कई वाहनों को टक्कर भी मारी। करीब लंबे रोमांचक पीछा करने के बाद वाघबीळ स्थित विजय गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास कार को रोकने में सफलता मिली। आरोपी कार छोड़कर भागने लगा, तभी पुलिस शिपाई अश्रु हाके ने उसे पकड़ने की कोशिश की। हालांकि आरोपी का शर्ट हाके के हाथ में आ गया और वह भीड़भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने चोरी की कार को कब्जे में लेकर कापुरबावड़ी ट्रैफिक विभाग पहुंचाया। बाद में कार मालिक राहुल जाधव से संपर्क कर घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद बेलगांव पुलिस के साथ पहुंचे वाहन मालिक को उनकी कार सौंप दी गई।

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने EVs का इस्तेमाल शुरू किया, गाड़ियों की संख्या कम की

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जवाब दिया

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
ठाणे। कोविड काल में देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और इसी वजह से भारत कोविड संकट से सुरक्षित बाहर निकला। अब देश के सामने जो युद्ध जैसे हालात बने हैं, उसमें भी नागरिकों को देश के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की अपील पर रिस्पॉन्स देना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा। वे ठाणे में रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशवासियों से फ्यूल बचाने की अपील के बाद मोदी ने आज से इस पर अमल करना शुरू कर दिया। उनकी अपील पर तुरंत रिस्पॉन्स देते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी EVs का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। आज उन्होंने अपने घर से सह्याद्री गेस्ट हाउस जाने के लिए EV का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेड़े में गाड़ियों की संख्या भी कम कर दी गई है।

उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी सुरक्षा

देश के हित के लिए फ्यूल बचाने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील; विपक्ष राजनीति न करे

करने वाले सिक्योरिटी गाड्र्स की गाड़ियों के अलावा कोई और गाड़ी अपने पास नहीं रखेंगे।इस मौके पर बोलते हुए शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश से किफ़ायत की योजना बनाने की अपील की है। उन्होंने खास तौर पर पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल कम करके फ्यूल बचाने पर ध्यान देने की ज़रूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए अपना खर्च कम करने के लिए हर भारतीय नागरिक को फ्यूल का कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव नतीजों का ज़िक्र किया और कहा कि लोगों को मोदी की लीडरशिप पर भरोसा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आलोचना की। शिंदे ने अपील की, देश की जनता समझदार है। 'वह पब्लिक है, सब जानती है', इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति किए बिना देशहित के लिए सरकार की अपील का समर्थन करना चाहिए। शिंदे ने बताया, "मोदीजी हमेशा 'देश को सबसे पहले' ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। इसीलिए मैंने आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राज्य में शिवसेना के सभी मंत्रियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।"उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर पूरी क्षमता से काम कर रही है। उन्होंने कहा, "इस अपील के पीछे मुख्य मकसद यह है कि देश के नागरिक युद्ध जैसी स्थिति से कम से कम प्रभावित हों।"इस मौके पर विपक्ष की आलोचना करते हुए शिंदे ने कहा कि ऐसी नाजुक स्थिति में राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, "राजनीति करने के कई अलग-अलग मौके हैं, लेकिन देश के हित के मुद्दों पर सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। विपक्ष सिर्फ़ मोदीजी को बदनाम करने के लिए आलोचना कर रहा है।

मंत्रियों और विभागों ने विदेश दौरों में कटौती की

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर प्रतिक्रिया देने का फैसला करने के बाद, मंत्री शंभूराज देसाई ने भी घोषणा की है कि वह अपने परिवार का यूरोप दौरा रद्द कर रहे हैं। दूसरी तरफ, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी डेनमार्क में आयोजित विदेश दौरे को कैंसिल करने का फैसला किया है। इसलिए, यह साफ है कि डिप्टी सीएम शिंदे और शिवसेना के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जवाब दिया है।

भूमि वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अतिक्रमण के खिलाफ सांसद सुरेश म्हात्रे आक्रामक

अदालत की अवमानना पर अधिकारी मौन क्यों?..

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता
भिवंडी । मुंबई-नाशिक महामार्ग पर पिंपळास गांव की सीमा में स्थित भूमि वर्ल्ड' गोदाम संकुल के अवैध निर्माण पर राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर सांसद सुरेश म्हात्रे (उर्फ बाळ्या मामा) ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि इस अवैध निर्माण को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, यही वजह है कि 6 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद भी एमएमआरडीए और जिलाधिकारी प्रशासन चुप्पी साधे बैठे हैं।

बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद सुरेश म्हात्रे ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन अगले दो दिनों के भीतर भूमि वर्ल्ड के डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, तो स्थानीय किसानों के साथ मिलकर उस निर्माण स्थल पर तीव्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी एमएमआरडीए

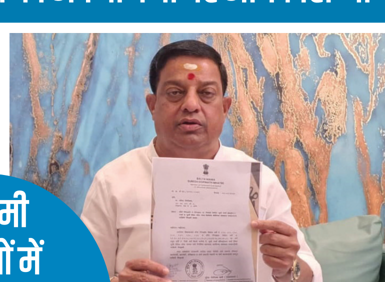

आगामी 15 दिनों में स्थानीय किसानों के सहयोग से होगा उग्र आंदोलन

और जिला प्रशासन की होगी।
भिवंडी तहसील के ठाणे-भिवंडी बाईपास रोड पर स्थित पिंपळास गांव में, भूमि वर्ल्ड के डेवलपर प्रकाश पटेल ने लगभग 1 करोड़ वर्ग फुट का निर्माण किया है। आरोप है कि इसमें शासन की 25 एकड़ चरवाहा भूमि और स्थानीय किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया है।

मुख्य सड़क पर साढे पांच लाख वर्ग फुट का एक मॉल बनाया गया है, जो 100% अवैध है। एमएमआरडीए ने स्वयं आरटीआई के तहत सांसद सुरेश म्हात्रे को लिखित में सूचित किया है कि इस निर्माण के लिए डेवलपर ने कोई अनुमति नहीं ली थी।

सांसद म्हात्रे ने आरोप लगाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018, 2019 और 2021 में दायर याचिकाओं के दौरान आदेश दिया था कि कोई भी नया निर्माण न किया जाए और एमएमआरडीए तत्काल अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे। इसके बावजूद प्रशासन अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इतना बड़ा अवैध निर्माण बिना प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। आज मैं ईमेल के माध्यम से ठाणे जिलाधिकारी को अंतिम अनुरोध कर रहा हूँ। यदि दो दिनों में कार्रवाई नहीं हुई, तो अगले 15 दिनों के भीतर किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। यदि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा।

सुरेश म्हात्रे (सांसद) सांसद म्हात्रे ने अंत में स्पष्ट किया कि वे न केवल डेवलपर के खिलाफ, बल्कि इस अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे।

पानी बचाने के नारों का शहर में शोर है

मगर मुंब्रा के जलकुंभ में सड़ांध और रिसाव का दौर है

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
ठाणे। ठाणे, मुंब्रा पाणी पुरवठा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, टूटी टंकियां और फटी पाइप लाइन से हजारों लीटर पानी बर्बाद। मुंब्रा में पानी संकट को लेकर समय-समय पर आंदोलन और राजनीति करने वाले नेताओं के दावों के बीच पाणी पुरवठा विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिस जल भंडारण केंद्र से हजारों नागरिकों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता है, वहीं की टंकियों की हालत बेहद खराब और चिंताजनक दिखाई दे रही है।

स्थानीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि पानी स्टोर करने वाली बड़ी टंकियों के लोहे के ढक्कन पूरी तरह जर्जर और सड़े हुए हैं। कई जगहों पर ढक्कन टूट चुके हैं, जिससे टंकी के अंदर सीधे धूल-मिट्टी और गंदगी जा रही है।

सबसे हैरानी की बात यह है कि टंकियों के आसपास किसी प्रकार का

सुरक्षा कवच या जाली तक मौजूद नहीं है, जिससे चूहे या छोटे जानवर आसानी से अंदर गिर सकते हैं। आसपास फैली गंदगी को देखकर यह आशंका भी जताई जा रही है कि अब तक कई चूहे या अन्य जानवर टंकियों में गिर चुके होंगे। सवाल यह उठता है कि क्या इसी गंदे और असुरक्षित सिस्टम का पानी मुंब्रा की जनता पीने को मजबूर है? इतना ही नहीं, पाणी पुरवठा विभाग के कार्यालय परिसर में भी भारी गंदगी देखी गई। विभाग की सफाई व्यवस्था पूरी तरह लचर नजर आई, जबकि यही विभाग जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर, विभाग के बाहर मुख्य पाइप लाइन पिछले कई महीनों से टूटी हुई बताई जा रही है।

पाइप लाइन से लगातार बड़ी मात्रा में पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इसकी मरम्मत करना जरूरी नहीं समझा। विडंबना यह है कि शहर में पानी को लेकर आंदोलन करने वाले कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इस टूटे पाइप लाइन और हजारों लीटर बर्बाद हो रहे पानी को शायद देख नहीं पा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर आंदोलन सिर्फ कैमरों तक सीमित हैं या वास्तव में पानी बचाने की कोई गंभीर चिंता भी है? मुंब्रा के नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की तत्काल जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और जल भंडारण केंद्र की सफाई, सुरक्षा तथा टूटी पाइप लाइन की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए।

Tata Motors ने लॉन्च की ऑटोमैटिक CNG कार

Tata Altroz iCNG अब AMT में भी उपलब्ध

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता
मुंबई। Tata Motors ने अपनी प्रीमियम हैचबैक Tata Altroz iCNG में अब एएमटी (ऑटोमैटिक) ट्रांसमिशन लॉन्च किया है। 8.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ यह भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक बन गई है, जो सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प देती है।

नई अल्ट्रोज़ iCNG AMT में 1.2 लीटर इंजन, 73.5 पीएस पावर और 103 एनएम टॉर्क मिलता है। इसमें डायरेक्ट CNG स्टार्ट, ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी और 210 लीटर बूट स्पेस जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

कार में फ्लश डोर हैंडल, एलईडी लाइट्स, 26.03 सेमी ट्विन डिजिटल स्क्रीन और प्रीमियम इंटीरियर के साथ 6 एयरबैग, ईएसपी और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के अनुसार यह मॉडल माइलेज, आराम और सुरक्षा का बेहतर संतुलन देगा।

जसलोक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में दुर्लभ हर्निया की सफल सर्जरी

महिला के सीने में पहुंच गए थे लीवर और आंतें

आर .एस. नेटवर्क। संवाददाता
मुंबई। जसलोक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने 32 वर्षीय महिला का दुर्लभ और जटिल डायफ्रामेटिक हर्निया का सफल ऑपरेशन किया। इस बीमारी में लीवर, पेट और आंतों का हिस्सा सीने में पहुंच गया था, जिससे फेफड़े पर दबाव बढ़ गया और मरीज को सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही थी।

करीब 10 घंटे चली सर्जरी में डॉक्टरों ने सीने में खिसके अंगों को वापस पेट में स्थापित किया और डायफ्राम के 20 सेंटीमीटर बड़े छेद की मरम्मत की। अस्पताल के अनुसार वयस्कों में इस तरह के मामले बेहद दुर्लभ हैं और दुनिया भर में अब तक ऐसे केवल 173 केस दर्ज किए गए हैं।

सर्जरी का नेतृत्व डॉ. विमेश राजपूत और डॉ. नीलेश ने किया। ऑपरेशन के बाद मरीज 9 दिन वेंटिलेटर पर रहीं, लेकिन तीन हफ्तों में उनकी हालत में तेजी से सुधार हुआ और वह बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चलने लगीं।

भिवंडी ग्रामीण इलाके में काम पर जा रहे व्यक्ति की निर्मम हत्या

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
भिवंडी । भिवंडी तालुका के शेडगाव में नाइट शिफ्ट में काम पर जा रहे एक व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान परेश तोलाराम पाटिल (उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परेश पाटिल हमेशा की तरह अपने घर से नाइट शिफ्ट के लिए काम पर निकले थे। उनके गांव की सीमा में ही घात लगाकर बैठे अज्ञात आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि परेश पाटिल की मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना के संबंध में गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

गणेशपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक कमलेश बच्छाव के मार्गदर्शन में हमलावरों और हत्या के कारणों की तलाश की जा रही है।

काटई से खोणी-खाडीपार ग्रामपंचायत सीमा में गतिरोधकों की भरमार

नागरिकों में भारी आक्रोश

आर.एस.नेटवर्क संवाददाता
भिवंडी। काटई से खोणी-खाडीपार ग्रामपंचायत क्षेत्र में अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में गतिरोधक लगाए जाने के कारण स्थानीय नागरिकों में गहरा गुस्सा देखा जा रहा है। नागरिकों ने इन गतिरोधकों को तुरंत हटाने की मांग की है। काटई से खोणी मार्ग पर सीमेंट और रबर के लगभग 15 से 16 गतिरोधक बना दिए गए हैं। सड़क पर इतने अधिक अवरोधों के कारण वाहन चालकों और विशेष रूप से रिक्शा से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सीमेंट के गतिरोधक टूट चुके हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटना होने की संभावना काफी बढ़ गई है। हाल ही में लगाए गए नए रबर के गतिरोधकों की वजह से यात्रियों को पीठ और कमर दर्द की शिकायतें होने लगी हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में हर 100 मीटर के अंतराल पर गतिरोधक लगाए गए हैं। नागरिकों ने सवाल उठाया है कि आखिर इतने अधिक गतिरोधकों की क्या जरूरत है? फिलहाल, संबंधित प्रशासन से इन गतिरोधकों को हटाकर वाहन चालकों और यात्रियों की असुविधा को दूर करने की मांग जोर पकड़ रही है।